SHRI VASANT SATHE: to which reply was already given.

SHRI SAMAR GUHA: Data in regard to what? In regard to certain steps. I wanted to know about those steps. Dereliction of duty does not mean an ethereal subject; it is a theoretical subject on the basis of certain happenings. Only on the basis of certain happenings if data and statistics are provided, can we ascertain whether there was dereliction of duty or not. That is the reason why I wanted the data connected with that.

MR. SPEAKER: I am not going to involve myself in arguments with you. Let him answer.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: My answer would still be the same that this question concerns itself specifically with senior officers being dealt with for any possible dereliction of duty. As regards the number of cases of riots that took place and what action was taken against any officers, if a separate question is tabled, I will answer.

स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्र पन्न देना

- *146. श्री लालजी भाई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगाठ के सिलसिले में भ्रब तक कुल कितने भीर किन किन लोंगों को तांग्र पत्न दिए जा चुके हैं।
- (ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई के 'सेवाग्राम' में प्रकाशित इस भ्राशय के समाचार की भ्रौर दिलाया गया है कि उनमें से 35 प्रतिशत व्यक्ति ताम्त्र पत्न पानें के ग्रिधिकारी नहीं हैं।
- (ग) क्या दिल्ली पुलिस की श्रपराध जांच शाखा ताम्र पत्न पाने वाले 36 व्यक्तियों के विरूद्ध जांच कर रही है; श्रीर
- (घ) यदि हां, तो तन्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

गृह-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ ० एच ० मोहिसिन): (क) श्रव तक उपलक्ष्म स्वना के श्रनुसार, 31 श्रक्तुबर, 1973 तक 33529 ताम्य पत्र प्रदान किए गये हैं। इन सभी व्यक्तियों के नाम देना सम्भव नहीं है। फिर भी, पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम तथा श्रन्य विवरण का प्रस्तुतीकरण के समय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र शासनों द्व।रा काी प्रचार किया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ): इस शिकायत के सम्बध्न में जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के 36 व्यक्तियों को, जो पान नहीं थे, पैशन अथवा ताम्प्रपान दिए गये थे, दिल्ली पुलिस के माध्यम से दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई ह। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री घटल विहारी वाजपेयी : मोहसिन साहबंकी बहुत ग्रन्छी हिन्दी के लिए बघाई । उन को बहुत बहुत मुबारक हो।

श्री सासजी भाई: इस प्रणाली के झाधार पर 31 श्रक्तूबर, 1973 तक 33529 तास्प्र-पत्न प्रदान किए गए, जब कि उनमें से 35. प्रतिश्वत लोगं उस के झिधकारी नहीं थे, ऐसी गल्ती क्यों हुई ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर वीक्षित): श्राप के इस प्रश्न में कहा गया है कि 35 प्रतिशत ऐसे थे जो इस को पाने के पात नहीं थे। लेकिन हम ने ऐसा नही कहा है कि 35 प्रतिशत गलत लोंगों को दिया गया है। जिन लोगों के बारे में शिकायते मिली थी, उन के बारे में जांच हो रहीं है, जब जांच पूरी हो जाएगी, तब हम श्राप को सूचना दे सकेंगे।

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी: इनके सवाल का जबाब बीजिए—— कि कसौटी के ग्राधार पर दिया गया ?

20

श्री सालशी माई जिन 36 व्यक्यों के विरुद्ध जांच हो रही है। उनमें से कितने कांग्रेसी हैं, ग्रीर कितने दूसरे व्यक्ति हैं? दूसरा प्रशन— भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है।

श्री उमाशंकर दीक्षित: जब तक उन जित्र 6 केसच के बारे में सूचना न ग्राये, तक तब ान किस तरह का है —यह बताना हमारे प्रतिलिए सम्भव नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर: जिन लोगों को ताम्प्रपत्न दिए गये हैं, उन में कितने ऐसे हैं जिन्होंने ताम्प्रपत्न स्वीकार नहीं किए तथा स्वीकार न करने के कारण क्या थे?

SHRI F. H. MOHSIN: We have got a list of eight persons who have so far declined to accept the award of Tamrapatra.

श्री पी॰ जी॰ मावलंकर: ग्रपा को बछाई दिए जाने के बाद मैंने भी हिन्दी में शरू किया इस उम्मीद से कि श्राप हिन्दी के सवाल का का जवाब हिन्दी में ही बेंगे।

श्री एफ ॰ एच ॰ मोहसिन : ग्रगर श्राप हिन्दी में सुनना चाहते हैं तो हिन्दी में बोलूगां हमारे पास ऐसे 8 ग्रादिमयों की लिस्ट है जिन्होंने उसे लेने से इन्कार किया था। ग्रीर ग्राप नाम सुनना चाएं तो नाम भी बतला सकता हूं....

श्री पी० जी० मावलंकर: क्रुपया नाम : वतलाइये।

भी एफ॰ एच॰ मीहसिन

- 1. श्री घासीराम (राजस्थान)
- 2. श्रीमती भ्रन्जना देवी चौधरी
- 3. श्री जगन्नाथ कदकड़
- . 4. श्री नारायण पिल्ले
- ः इ. शीपी० के० कुंजू

- 6. श्री म्रच्युत नन्दन
- हरियाणा गवर्गमेंट ने नाम नहीं दिया है, लेकिन एक झादमी ने वहां रिसीव नहीं किया है।
- मीर मुश्ताक ग्रहमद

श्री पी० जी० मावलंकरः इन्होंने क्या कारण बतलाये हैं।

श्री एफं० एचः मोहसिन: ग्रगर मैं कारण बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। ग्रगर समय दिया जाए तो बतला सकता हूं।

श्री पीलू मोदी: मैं ब्राप के माध्यम से मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं—ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने तास्त्र-पन्न के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, उन के पिटकुलसं दिए गए थे, लेकिन फिर भी उन को नहीं मिले। मैं जानना चाहता हूं कि जिन के केस साबित भी हो चुके थे, फिर भी उनको किस कारण से नहीं दिए गए?

श्री एक॰ एच॰ मोहिसन: जो फीडम फाइटर्स हैं श्रीर जिन को पेन्शन मिल रही है उन सभी को तास्त्र-पत्न मिलना चाहिए। इन के ग्रलावा जिन की इन्कम 5 हजार से जादा हो, उन को भी मिलना चाहिए। ग्रव तक जिन को दिया गया है, उन की स्टेटबाइज लिस्ट बनाई गई हैं। ये तास्त्रपत्न राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं, सेन्ट्रल गर्वमेंन्ट से नहीं दिए जाते हैं।

SHRI PILOO MODY: Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, has distributed so many.

श्री एक एच मोहसिन : पहली मर्तवा 15 ग्राम्स्त , 1972 को चन्द लोगों को यहां पर प्रधान मंत्री जी द्वारा ताम्प्र-पात दिये गये— उस के बाद यहां ऐसा कोई फंकशन नहीं हुग्रा श्रीर राज्य सरकारें ही ये ताम्प्र-पात वितरण कर रही है।...

श्रा पोल मंदाः हम को फक्शन नहीं चाहिए, हम का ताम्म-पत्र चाहिए।

श्री एफ एक महिसिन : ग्राप मुझ को जवाब परा करने बाजिये। जिन स्टेटों में ताम्प्र-पत्न वितरण का काम ठाक तरह से नहीं हम्रा है, उन सभी राज्य सरकारों को होम मिनिस्टर साहव ने ताम्य-पन्न वितरण की द्यावश्यकता के बारे में लिखा है।

PROF. MADHU DANDAVATE: May I konw whether any members of the Royal Indian Navy who participated in the mutiny in 1946 have been awarded Tamrapatra? To the lasting shame of the nation, not a single man from the Royal Indian Navy has been given the Tamrapatra. Please let the Minister clarify this. (Interruption) It is a very important question. Let the Minister reply to that. (Interruption)

SHRI S. M. BANERJEE: I wanted to put the same question. It is with reference to those people who revolted here at the time of the Britishers. The British called it the mutiny. I would like to know whether it is a fact that none of those people who revolted against the British Empirethey were in the Royal Indian Navyhave been given the Tamrapatra. I would like to know whether it is true or not.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: May I give a little information on that subject? Because it was not possible for us to ascertain the exact merits of each case, a Committee has been appointed with Mr. Shahnawaz Khan as the Chairman to go into these cases, and there the INA personnel civilian . . (Interruption)

SHRI S. M. BANERJEE: I am talking of R.I.N.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: I am sorry.

SHRI F. H. MOHSIN: We have got a total list of persons who have been awarded. We have no separate list of those people...(Interruptions)

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GAN-DHI): Both the INA personnel and the unit of the Royal Navy are included in the pension scheme and, therefore they should also be eligible for Tamrapatra. Whether they have been given or not, we shall have to enquire from the State Governments.

Pending Applications for Industrial Licences

- *149 SHRI K. S. CHAVDA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVE-LOPMENT AND SCIENCE AND TE-CHNOLOGY be pleased to state:
- (a) the present position of pending applications for Industrial Licences to be categorised as under:
 - (i) pending for over three months. but less than six months:
 - (ii) pending for six months and over but less than 12 months;
 - (iii) pending for tweleve months and over; and
- (b) when the applications pending for over twelve months are expected to be disposed of?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVE-LOPMENT (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) As on 1st November 1973, 724 applications were pending for over 3 months but less than 6 months, 881 applications were pending for over 6 months but less than 12 months and 1472 applications were pending for over 12 months.

(b) Every effort is being made to dispose of these applications as expeditiously as possible.

SHRI K. S. CHAVDA: Government has since laid down a revised procedure for the disposal of applications received on or after 1st November